



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293]	नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 23, 2019/आश्विन 1, 1941
No. 293]	NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 23, 2019/ASVINA 1, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच की शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2019

[सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम 6 के तहत]

(रक्षोपाय जांच)

[मामला संख्या: (एसजी) 05/2019]

विषय: भारत में "सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर" के आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच की शुरुआत की सूचना ।

फा.सं. 22/5/2019-डीजीटीआर.—मैसर्स स्टारलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड ('एसटीएल') और मै. बिरला फुरूकावा फाइबर ऑप्टिक प्राइवेट लिमिटेड ('बीएफएल') (जिन्हें यहां आगे "याचिकाकर्ता" अथवा "आवेदक" भी कहा गया है) ने मैसर्स टीएलसी लीगल एडवोकेट्स नई दिल्ली के माध्यम से समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं मूल्यांकन) नियमावली, 1997 (जिसे यहां आगे "नियमावली" या रक्षोपाय नियमावली भी कहा गया है) के नियम 5 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे अधिनियम भी कहा गया है) एक आवेदन दायर किया गया है जिसमें उन्होंने "सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर" (जिसे यहां आगे "एसएमओएफ" या "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" अथवा संबद्ध सामान भी कहा गया है) जिसके कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो रही है और गंभीर क्षति होने का खतरा है। उन्होंने एसएमओएफ ऐसे बड़े हुए आयातों के कारण गंभीर क्षति और गंभीर क्षति के खतरे से समान वस्तु या सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पादों के घरेलू उद्योग का संरक्षण करने के लिए रक्षोपायों को लागू करने की मांग की है।

- विचाराधीन उत्पाद:** विचाराधीन उत्पाद "सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर" है, जिसका अर्थ सिंगल स्पेशल मोड के लिए एक कैरियर के रूप में ट्रांसमिशन को सुकर बनाने के लिए प्रयुक्त ऑप्टिकल फाइबर है और इसका प्रयोग कतिपय बैंडों

के भीतर सिंगल ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। मानकीकृत सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर प्रकारों में नॉन डिस्पersion शिफ्टेड फाइबर (जी.652), डिस्पersion शिफ्टेड फाइबर (जी.653), कट ऑफ शिफ्टेड सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर जी.654 और नॉन जीरो डिस्पersion शिफ्टेड फाइबर (जी. 655 और जी. 656) तथा बैंड असंवेदी सिंगल मोड फाइबर (जी.657) शामिल हैं। संबद्ध वस्तु का प्रयोग मुख्यतः ऑप्टिकल फाइबर टेबल के निर्माण में होता है। संबद्ध उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के टैरिफ शीर्ष 9001 (90011000) के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त एसिड कोड केवल सांकेतिक है और उत्पाद का विवरण सभी परिस्थितियों में लागू होगा।

3. **घरेलू उद्योग (डीआई):** यह आवेदन मैसर्स स्टर्लाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड ('एसटीएल') और मै. बिरला फुरूकावा फाइबर ऑप्टिक प्राइवेट लिमिटेड ('बीएफएल') द्वारा एसएमओएफ के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए दायर किया गया है। आवेदकों के पास भारत में घरेलू समान वस्तु के कुल उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है। दोनों उत्पादक सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 बी की उप धारा (6) के खंड (ख) के अनुसार घरेलू उद्योग हैं।
4. **जांच की अवधि:** वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए मानी गई अवधि (पीओआई) 2016-17 से जून, 2019 तक है। आवेदकों ने 2018-19 में आयातों में अचानक तेज और भारी उछाल का दावा किया है जो उसके बाद भी जारी रहा है। प्राधिकारी ने 6 महीने की अवधि (अर्थात् जनवरी, 19-जून, 19) को सबसे हाल की अवधि के रूप में लिया है।
5. **बढ़े हुए आयात:** याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि 2018-19 में आयातों में अचानक तेज और भारी वृद्धि हुई है जो समग्र रूप से तथा घरेलू उद्योग के उत्पादन की दृष्टि से हुई है। यह नोट किया जाता है कि 2018-19 में आयात (गैर-डीआई) 2016-17 और 2017-18 के स्तरों से तीन गुना से अधिक बढ़ गए हैं और बिल्कुल हाल की अवधि अर्थात् जनवरी, 19 से जून, 19 के दौरान इनका उच्च स्तर पर रहना जारी है। संबद्ध वस्तु के आयातों में संबद्ध वस्तु के आयातों में वृद्धि की दर पी ओ आई और बिल्कुल हाल की अवधि के दौरान उसकी मात्रा पर विचार करते हुए काफी अधिक मानी गई है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि अनेक गतिविधियों जैसे फाइबर उद्योग में वैश्विक अधिक क्षमता, चीन द्वारा अधिकांश ऑप्टिकल फाइबर के विनिर्माता देशों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाने और चीन निर्मित ऑप्टिकल फाइबर की बिक्री/प्रयोग पर लागू अन्य राजकोपीय/गैर-राजकोपीय प्रतिबंधों के एक साथ होने के कारण भारत में आयातों का अचानक विपथन हुआ है।
6. **घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति तथा गंभीर क्षति का खतरा:** आवेदकों ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए आयातों से घरेलू उत्पादकों को क्षति हुई है तथा गंभीर क्षति होने का खतरा भी हो रहा है। आवेदकों ने दावा किया है कि भारतीय बाजार में पी ओ आई के दौरान मांग बढ़ी है और वह बिल्कुल हाल की अवधि में भी बढ़े हुए स्तर पर बनी रही है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि स्वतंत्र उपभोक्ता (अर्थात् आबद्ध/संबंधित पक्ष की बिक्री/ डी आई के आयातों को छोड़कर घरेलू बिक्री) को उनकी बिक्री में पी ओ आई तथा बिल्कुल हाल की अवधि के दौरान भारी गिरावट आई है। आवेदकों ने यह भी बताया है कि स्वतंत्र उपभोक्ताओं के भारतीय मांग में उनके हिस्से में भी बिल्कुल हाल की अवधि अर्थात् जनवरी-जून, 19 में भारी गिरावट आई है जबकि आयातों के हिस्से में भारी वृद्धि हुई है। आवेदकों द्वारा यह भी बताया है कि घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग बिल्कुल हाल की अवधि अर्थात् जनवरी-जून, 19 में भी घटा है उन्होंने यह भी दावा किया है कि पी ओ आई के दौरान उनकी लाभप्रदता में भी गिरावट आई है और बिल्कुल हाल की अवधि में वे घाटे में चल रहे हैं। यह भी दावा किया गया है कि आयातों के कम कीमत में आने के कारण आवेदक कंपनियों को उपभोक्ताओं द्वारा उनकी कीमतें कम करने को बाध्य किया गया है जिसके परिणामस्वरूप बिल्कुल हाल की अवधि में काफी कीमत ह्रास और न्यूनीकरण हुआ है। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि घरेलू उद्योग के पास संबद्ध वस्तु की मालसूची में भी भारी वृद्धि हुई है।
7. आवेदकों ने घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति और/या गंभीर क्षति का खतरा पहुँचाने वाले संबद्ध वस्तु के आयातों में काफी वृद्धि को देखते हुए अनंतिम रक्षोपाय शुल्क तत्काल लगाए जाने का अनुरोध किया है।
8. आवेदकों द्वारा दायर आवेदन पत्र की जांच करने के बाद महानिदेशक प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि संबद्ध वस्तु के आयातों में 2018-19 और बिल्कुल हाल की अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है और यह वृद्धि अप्रत्याशित गतिविधियों जैसे फाइबर उद्योग में वैश्विक अधिक आपूर्ति, चीन जन.गण. द्वारा अधिकांश ऑप्टिकल फाइबर के विनिर्माता देशों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाने और चीन निर्मित ऑप्टिकल फाइबर की बिक्री पर लागू अन्य प्रतिबंधों के

परिणामस्वरूप हुई है और यह कि इन आयातों की मात्रा और कीमतों के कारण घरेलू उद्योग को भारी क्षति हुई है और/या होने का खतरा है।

जांच शुरूआत

9. यह निर्धारित करने के बाद कि रक्षोपाय जांच की शुरूआत को न्यायोचित बनाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। महानिदेशक रक्षोपाय नियमावली, 1997 के नियम 5 के अनुपालन में जांच की शुरूआत करते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या अप्रत्याशित गतिविधियों के परिणामस्वरूप विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि हुई है और क्या बढ़े हुए आयातों के कारण समान और और/या सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पादों के घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है और/या होने का खतरा है।
10. सभी हितबद्ध पक्षकार इस सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत करा सकते हैं:

महानिदेशक
व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर)
जीवन तारा बिल्डिंग, चौथा तल,
5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली 110001

11. सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को अलग से भी लिखा जा रहा है।
12. जांच से संबंधित कोई भी अन्य पक्षकार जो हितबद्ध पक्षकार माना जाना चाहता हो, अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है जो इस सूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर उपर्युक्त पते पर महानिदेशक को पहुँच जाए।
13. यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो महानिदेशक रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं। सूचना हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
14. **गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना** – महानिदेशक के समक्ष कोई अनुरोध (परिशिष्टों/उससे संलग्न अनुलग्नक सहित), प्रश्नावली के उत्तर सहित प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से अपेक्षा है कि वे उन्हें दो अलग-अलग सेटों में, यदि उसके किसी भाग में "गोपनीयता" का दावा किया गया है, दायर करें। "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। इस प्रकार की मार्किंग के बिना किया गया कोई भी अनुरोध महानिदेशक द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और महानिदेशक उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों रूपांतरों की सॉफ्ट प्रतियाँ भी प्रत्येक के दो (2) सेटों में हार्ड प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा। गोपनीय रूपांतर में वह सभी सूचना होगी जो प्रकृति में गोपनीय हैं और/अथवा अन्य सूचना होगी जो उस सूचना को देने वाला गोपनीय होने का दावा करता है, जिस सूचना को प्रकृति में गोपनीय होने का दावा किया जाए अथवा जिस सूचना के संबंध में अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचना देने वाले से यह अपेक्षा है कि वे दी गई सूचना के साथ उसका सही कारण का विवरण दें कि उस सूचना को प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता। अगोपनीय रूपांतर में गोपनीय सूचना के साथ, अधिमानतः सूचीबद्ध अथवा खाली रखा गया (यदि सूचीकरण व्यवहार्य नहीं है) और जिस सूचना के संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है, उस पर आधारित सार का प्रदर्शन होना अपेक्षित है। अगोपनीय सार में गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के सार को उपयुक्त रूप से समझने के लिए पर्याप्त ब्यौरे होने चाहिए। तथापि, अपवादस्वरूप परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि वह सूचना सार में अतिसंवेदनशील नहीं है और कारणों का यह विवरण कि उसका सार करना क्यों संभव नहीं है, महानिदेशक की संतुष्टि के अनुसार दिया जाना चाहिए। महानिदेशक प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के लिए अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि महानिदेशक संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है और यदि सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक करने का इच्छुक नहीं है अथवा उसे सामान्यीकृत अथवा सार रूप में प्रकट करने के लिए प्राधिकृत करता है, तो वे उस सूचना को अनदेखा कर सकते हैं। कोई भी अनुरोध, जो उसके सार्थक अगोपनीय रूपांतर के बिना किया गया है अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में सही कारणों के विवरण के बिना किया गया है, महानिदेशक द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा। महानिदेशक संतुष्ट होने पर तथा दी गई सूचना की

गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर उसे सूचना देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को प्रकट नहीं करेंगे।

15. कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।
16. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में पर्याप्त व्यवधान डालता है तो महानिदेशक उनके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं और केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिश कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2019

[Under Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997]

(Safeguard Investigation)

[Case No: (SG) 05/2019]

Subject: Notice of initiation of Safeguard Investigation concerning imports of “Single Mode Optical Fibre” into India

F. No. 22/5/2019-DGTR.—An application has been filed by M/s Sterlite Technologies Limited (‘STL’) and M/s Birla Furukawa Fibre Optics Private Limited (‘BFL’) (hereinafter also referred to as the “Petitioners” or “Applicants”) through M/s TLC Legal Advocates, New Delhi in terms of Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter also referred to as “Act”) read with Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 (hereinafter also referred to as “Rules” or “safeguard rules”), as amended from time to time, alleging increased imports of “Single Mode Optical Fibre” (hereinafter also referred to as “SMOF” or “product under consideration” or “PUC” or subject goods) causing serious injury and threat of serious injury to the domestic industry. They have sought imposition of safeguard measures to protect the Domestic Industry of like article or directly competitive products from serious injury and threat of serious injury being caused by such increased imports of SMOF.

2. **Product under Consideration:** The product concerned is “Single-mode Optical Fibre” which refers to the Optical Fibre used to facilitate transmission of a single spatial mode of light as a carrier and is used for signal transmissions within certain bands. The standardized single mode optical Fibre types include the Non-dispersion shifted Fibre (G.652), Dispersion shifted Fibre (G.653), Cut-off shifted single mode optical Fibre (G.654), and Non Zero Dispersion Shifted Fibre (G.655 & G.656) as well as Bend insensitive single mode Fibre (G.657). The subject goods are mainly used for manufacturing Optical Fibre Cable. The subject products are classifiable under Tariff Heading 9001 (90011000) of the first schedule of Customs Tariff Act, 1975. It is clarified that the said HS code is indicative only and the product description shall prevail in all circumstances.
3. **Domestic Industry (DI):** The application has been filed by M/s Sterlite Technologies Limited (‘STL’) and M/s Birla Furukawa Fibre Optics Private Limited (‘BFL’) for imposition of Safeguard Duty on imports of SMOF. The applicants account for a major share of the total production of the domestic like article in India. The two producers constitute Domestic industry in terms of Clause (b) of the sub-section (6) of Section 8B of the Custom Tariff Act, 1975.
4. **Period of Investigation:** The period of investigation (POI) considered for the purposes of present investigation is from 2016-17 to June 2019. The Applicants have submitted that there has been a sudden, sharp and significant surge in imports in 2018-19, which has continued thereafter as well. The Authority has taken six months period (i.e. January’ 19 - June’ 19) as the most recent period.
5. **Increased Imports:** The petitioners have claimed that there is a sudden, sharp and significant increase in imports in 2018-19 both in absolute terms as well as relative to DI production. It is noted that the imports (Non-DI) in 2018-19 have more than tripled from 2016-17 and 2017-18 levels and have continued to be at increased levels during the most recent period, i.e. January’ 19 to June’19. The rate of increase in imports of subject goods is

considered significant, considering their quantum during the POI and most recent period. The Petitioners have claimed that there is a confluence of a number of developments such as global over-capacity in Fibre industry, imposition of anti-dumping duty by China against most of the Optical Fibre manufacturing countries, and other fiscal/ non-fiscal restrictions imposed on sale/ use of China-made Optical Fibre, which has resulted in sudden diversion of imports to India.

6. **Serious Injury and threat of serious injury to the domestic industry:** The applicants have claimed that the increased imports of 'PUC' has caused and is threatening to cause serious injury to the domestic producers of 'PUC'. The Applicants have claimed that the demand in Indian market has increased during the POI and have continued to remain at increased level in the most recent period as well. They have also claimed that their sales to independent customers (i.e. domestic sales excluding captive/ related party sales/ DI imports) has substantially gone down during the POI as well as the most recent period. The Applicants have also submitted that their share in Indian demand for independent customers has declined significantly in the most recent period (i.e. in January-June'19), whereas the share of imports has increased drastically. The Applicants have further submitted that the Capacity utilization of the domestic industry has also declined in the most recent period (i.e. Jan-Jun' 19). They have also claimed that their profitability has considerably declined during the POI and they are running in losses in the most recent period. It has also been claimed by the applicants that because of the imports coming at low prices, the applicant companies were forced by their customers to reduce their prices resulting in significant price depression and suppression in the most recent period. The applicants have also claimed that there is a significant increase in inventories of subject goods lying with the domestic industry.
7. The applicants have requested for immediate imposition of provisional safeguard duty in view of significant surge in imports of subject goods causing serious injury and/or threatening to cause serious injury to the domestic industry.
8. After examining the application filed by applicants, the Director General, prima facie, finds that there is a significant increase in imports of subject goods during 2018-19 and the most recent period, and such increase appears to be a result of unforeseen developments such as global oversupply, anti-dumping duty imposed by China PR against major Optical Fibre producing countries and other restrictions imposed on sale of China-made Optical Fibre, and that the volume and prices of these imports have caused and/or are threatening to cause significant injury to domestic industry.

Initiation

9. After determining that there is sufficient evidence to justify initiation of safeguard investigation, the Director General initiates an investigation pursuant to rule 5 of the Safeguard rules, 1997 in order to determine whether as a result of unforeseen developments, the imports of the product under consideration constitute increased imports, and whether the increased imports have caused and/ or are threatening to cause serious injury to the domestic industry of like and/or directly competing products.
10. All interested parties may make their views known within a period of 30 days from the date of this notice to:

Director General
Directorate General of Trade Remedies (DGTR),
Jeevan Tara Building, 4th Floor,
5, Parliament Street,
New Delhi -110001

11. All known interested parties are also being addressed separately.
12. Any other party to the investigation who wishes to be considered as an interested party may submit its request so as to reach the Director General on aforementioned address within 30 days from the date of this notice.
13. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Director General may record its findings on the basis of the facts available on record. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.
14. **Submission of Information on Confidential Basis –** The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the Director General including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Director General and the Director General shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in two (2) sets of each. The confidential version shall contain all information which are by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. The information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the

information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Director General. The Director General may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Director General is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Director General. The Director General on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

15. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.
16. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Director General may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Director General